

MPC ने रेपो रेट को अपरविरतति रखा

प्रलमिस के लयि:

[भारतीय रज़िरव बैंक](#), [बैंकगि कषेतर और NBFC](#), [संप्रभु/सॉवरेन हरति बॉण्ड](#), [मौद्रकि नीतिसमति](#), [राजकोषीय नीत](#), [रेपो रेट](#), [मुद्रासफीत](#)

मेन्स के लयि:

राजकोषीय नीत और मौद्रकि नीत में ब्याज दर का महत्त्व

स्रोत: [इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#) की [मौद्रकि नीतिसमति \(MPC\)](#) ने अपनी बैठक में ब्याज दरों को अपरविरतति रखने के लयि मतदान कयि, जबकि रेपो रेट 6.5% पर है।

समति ने ऋण की वापसी (withdrawal of accommodation) पर ध्यान केंद्रति रखने का भी नरिणय लयि।

नोट:

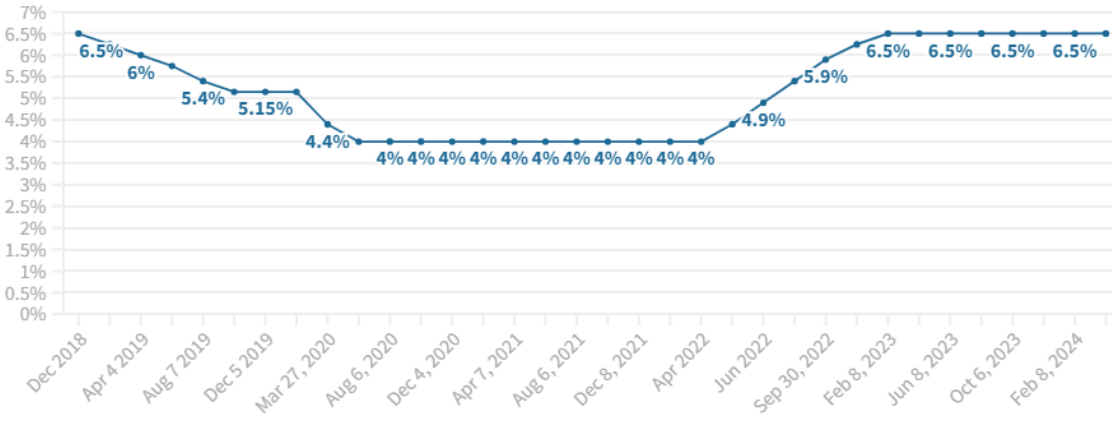
- ऋण मौद्रकि नीत: एक ऋण रुख (stance) का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक आर्थकि वकिस को बढ़ावा देने के लयि धन आपूरतिका वसितार करने के लयि तैयार है।
- ऋण नीत की वापसी का अर्थ है प्रणाली में धन की आपूरत में कमी, जससे मुद्रासफीत पर नरिंतरण कयि जा सकेगा।

MPC बैठक के परणाम क्या हैं?

- RBI ने [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय \(NSO\)](#) द्वारा अनुमानति 7.6% वृद्धि के मुकाबले वत्तीय वर्ष 2025 के लयि GDP वृद्धिका अनुमान 7% पर बरकरार रखा है।
 - इसने वत्तीय वर्ष 25 की पहली तमाही में 7.1%, Q2 में 6.9 प्रतशित और Q3 और Q4 में 7% की वृद्धिका अनुमान लगाया है।
- MPC ने तरलता समायोजन सुवधि (LAF) के तहत नीत आधारति रेपो रेट को 6.50% और [स्थायी जमा सुवधि \(SDF\)](#) को 6.25% पर अपरविरतति रखने का नरिणय लयि।
- MPC वकिस के उद्देश्य का समर्थन करते हुए मुद्रासफीत को +/- 2% के बैंड के भीतर 4% लक्ष्य के साथ संरेखति करने के लयि प्रतबिद्ध है।

RBI repo rate

The repo rate is the interest rate at which the RBI lends to commercial banks.



ब्याज दरें अपरविरतति रखने के क्या कारण हैं?

■ खाद्य मुद्रास्फीति:

- उच्च खाद्य मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति को उच्च रखती है, भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर कमी देखी गई है।
- वैश्विक अनश्चितताओं और अल-नीनो के प्रभाव के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनश्चितताएँ, चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- अगले वर्ष सामान्य मानसून के अनुमान के साथ-साथ रबी की फसल के बाज़ार में आने से भी खाद्य कीमतों पर दबाव कम होगा।
- हालाँकि सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों के दबाव के कारण खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है।

■ त्योहार का मौसम:

- त्योहार के मौसम में बढ़ी हुई मांग और त्योहार के दिनों में खपत बढ़ने के कारण बाज़ार में तरलता को बढ़ावा मिला।

■ कच्चे तेल की कीमतें और इनपुट लागत:

- कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक अनश्चितता के कारण परदृश्य अनश्चितता बना हुआ है।

■ लचीली आर्थिक गतिविधि:

- भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न कारणों से उत्पन्न अनश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित किया है।
- इसके चलते बेंचमार्क दरों को बनाए रखने का नरिणय लिया गया, जो संभावित आघातों को झेलने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।

■ पछिली नीति रेपो दर में वृद्धि:

- मौद्रिक नीति समिति ने स्वीकार किया कि पछिली नीतिगत रेपो दर वृद्धि अभी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में है।

■ मुद्रास्फीति जोखिम प्रबंधन:

- दरों को अपरविरतति रखना स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने हेतु तैयार रहने के लिये एक आवश्यक उपाय हो सकता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है?

■ परिचय:

- इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति दर के लिये एक लक्ष्य निर्धारित करता है और इसे प्राप्त करने के लिये मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है।
- भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढाँचा है जिसे वर्ष 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाया गया था।
- वर्तमान में RBI का प्राथमिक उद्देश्य 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना है। RBI के पास +/- 2% का एक सुविधा क्षेत्र है जिसके भीतर मुद्रास्फीति बनी रहनी चाहिये। इसका अर्थ है कि RBI का लक्ष्य मुद्रास्फीति दर को 2% से 6% के बीच रखना है।

■ सीमाएँ:

- अवसंरचनात्मक बाधाएँ: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आपूर्ति-पक्ष या संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में प्रभावी नहीं हो सकता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है जैसे कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जिससे उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।
- वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है (विशेष रूप से खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से पूंजी प्रवाह और वनिमिय दरें प्रभावित हो सकती हैं।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं (विशेष रूप से समाज के कमज़ोर लोगों पर), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से रोज़गार, आय और अन्य आर्थिक पहलू प्रभावित हो सकते हैं।
- सटीक आँकड़ों की उपलब्धता: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण हेतु मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक पहलुओं से संबंधित सटीक आँकड़ों

की आवश्यकता होती है। जो भारत सहित सभी देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है।



मौद्रिक नीति समिति

Monetary Policy Committee

मौद्रिक नीति समिति

- ★ **प्राधिकरण:**
 - ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, **1934** के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।
- ★ **उद्देश्य:**
 - ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- ★ **कानूनी ढाँचा:**
 - ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, **1934** की धारा **45ZB** के तहत।
 - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (**MPC**) का गठन करने का अधिकार है।
 - ★ **MPC** को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। **MPC** के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

संघटन

- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
 - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
 - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार **RBI** को मुद्रास्फीति के स्रोतों और **6-18** महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. रेपो दर को अपरवर्तित रखने के कारणों एवं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में मौद्रिक नीति समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2015)

1. बैंक दर
2. खुला बाज़ार परचिालन
3. सार्वजनकि ऋण
4. सार्वजनकि राजस्व

उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीतिका/के घटक है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीतिका अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

- 1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलति करना
- 2. सीमांत स्थायी सुवधि दर को बढ़ाना
- 3. बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुर्नत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mpc-keeps-repo-rate-unchanged>